वर्ष-10//अंक-23//अगस्त//2023
ISSN 2454–5805
RNI NO.: CHHHIN/2013/50684

आम आदमी पत्रिका

एक आम इंसान की सोच

टाटा टेक्नोलॉजीस के साथ एमओयू 10 हजार युवा होंगे लाभान्वित

अंबानी की कंपनी विदेशी बैंकों से लेगी 1.5 अरब डॉलर का कर्ज

दुग्ध कारोबार से किसानों पशुपालकों के जीवन में आई समृद्धि,

05

जेईई और नीट प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी सरकार ने उठाया बेहतरीन कदम

12

मानवता के लिए काम करता है: डॉ. मनोज अग्रवाल

20

चिरायु योजना से अलीना को मिला जीवनदान

www.aamaadmi.in

Chai Signal

MARINE DRIVE ki sham Chai Signal ke naam

अब मरीन ड्राइव Spree Walk में भी

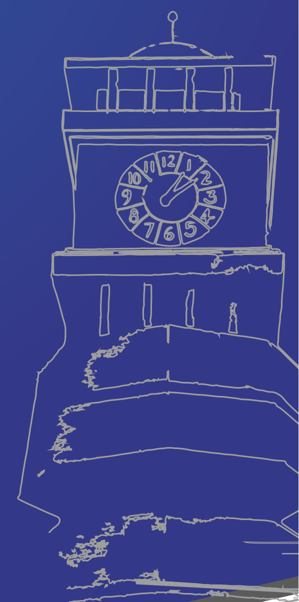

Kulhad Ki Chai

Indian Street Snacks, Sandwiches, Maggi
Coffee, Cold Coffee

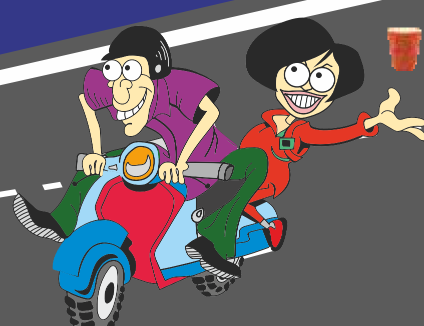

Add.: Marine Drive Spree Walk, (Beside Pizza Hut) Telibandha Talab, Raipur (C.G.)
Find us on @chaisignalcafe | www.chaisignal.com

आम आदमी पत्रिका

वर्ष-10//अंक-23//अगस्त//2023

प्रबंध संपादक	:	उमेश के बंसी
सर्कुलेशन इंचार्ज	:	प्रकाश बंसी
रिपोर्टर	:	नेहा श्रीवास्तव
कंटेंट राईटर	:	प्रशांत पारीक
क्रिएटिव डिजाइनर	:	देवेन्द्र देवांगन
मैग्ज़ीन डिज़ाइनर	:	आइज इवेंट्स
मार्केटिंग मैनेजर	:	किरण नायक
एडमिनिस्ट्रेशन	:	काजल सिंह
अकाउंट असिस्टेंट	:	प्रियंका सिंह
ऑफिस कॉर्डिनेटर	:	योगेन्द्र बिसेन

प्रधान कार्यालय

965/1 कक्कड़ चौक, श्याम नगर रोड,
कटोरा तालाब,रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन : 0771-4044047
ईल : khabar@aamaadmi.in

कार्यालय

प्लाट नं.118, कंचन बाग, राजनांदगांव

प्रकाशक

उमेश कुमार बंसी, क्वाटर नंबर 10, एम.एम.
रियल स्टेट कॉलोनी, अमलीडीह, रायपुर
(छत्तीसगढ़) से प्रकाशित एवं मुद्रित

विशेष- इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिये गए विचार, लेखकों के अपने है। इसमें संपादक / मुद्रक की सहमति अनिवार्य नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संपादक / मुद्रक जिम्मेदार नहीं होगा। इस पत्रिका से संबंधित किसी भी विवाद के लिए सुनवाई क्षेत्र रायपुर न्यायालय होगा।

अनुक्रमणिका

अगस्त 2023

इस अंक में

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने नवा रायपुर में प्रभावितों को पट्टा देने का फैसला किया है. बीमार और बंद उद्योगों को भी पैकेज देने का निर्णय किया गया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. इसमें सरकारी भर्ती में छूट देने के साथ ही उद्योगों की स्थापना में रियायत देने का फैसला किया गया है.

34

सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं से ग्रामीणों को हो रहा लाभ... 14

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली की खण्डपीठ द्वारा बाल अधिकार सम्बन्धी प्रकरणों के निराकरण हेतु शिविर आयोजित किया गया।

मछली पालन से बदली तकदीर और तस्वीर: 22

ये मेहनतकश और सरकार की सफल योजनाओं की तस्वीर है, जो खुशहाली की कहानी बयां कर रही है.

वनाश्रितों को मिला न्याय, वनोपज से बढ़ी आय 23

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जंगलों के बीच रहकर जीवन-यापन करने वालों के बारे में सोचा और तेंदूपते का समर्थन मूल्य बढ़ाया.

नन्हे मियान की लौटी मुस्कान: मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से मिला नया जीवनदान 26

मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत छत्तीसगढ़ को कुपोषण एवं एनीमिया मुक्त बनाने के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं.

सीएम भूपेश के नए पुलिस रेंज के गठन से छत्तीसगढ़ की पोलिसिंग में आएगा बड़ा बदलाव, 28

रायपुर. प्रदेश में आम जनता की सुविधा, बेहतर पुलिसिंग और आपराधिक प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए नए पुलिस रेंजों का गठन किया गया है.

शिक्षाकर्मी की नौकरी छोड़ कर मोहन मरकाम पहुंचे राजनीति में 32

छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री बनाए गए मोहन मरकाम शिक्षा कर्मी रहे हैं. वे बस्तर संभाग के कोंडगांव से दूसरी बार के विधायक हैं.

मणिपुर में अब और न बढ़े नफरत

उमेश के बंसी
(प्रबंध संपादक)

विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के 21 सांसदों ने मणिपुर पहुंचने के बाद अधिक से अधिक शरणार्थी शिविरों में रह रहे लोगों से सीधे मुखातिब होने के लिए दो टीम में बंटकर अपने काम को अंजाम दिया है. सदस्यों ने मैतेई और कुकी, दोनों समुदायों के शिविरों का जायजा लिया और वे जमीनी हकीकत से रूबरू हुए. मणिपुर में हिंसा अब भी जारी है. दोनों समुदायों के शरणार्थियों से बात करने पर यह बात स्पष्ट हो गई है कि इनमें एक-दूसरे के खिलाफ नफरत व डर की खाई और गहरी हो गई है. चुराचांदपुर, मोइरंग और इंफाल के शिविरों में रह रहे विस्थापितों ने बताया कि मणिपुर में अभी भी गोलियां चल रही हैं. लोगों के घर फूंके जा रहे हैं. बम के गोले फेंके जा रहे हैं. पहाड़ी, घाटी, मैदान हर तरफ हिंसा की आग सुलग रही है.

मणिपुर में दुर्गम पहाड़ों पर पहुंचना आसान नहीं है. ऐसे स्थानों पर हेलीकॉप्टर से ही पहुंच सकते हैं. इन इलाकों का मंजर तो और भी भयावह है. मैतेई व कुकी अपने-अपने इलाके का सीमांकन करके नहीं रहते हैं. एक ही जगह दोनों ही समुदायों की आबादी बसती है. सुदूर पहाड़ों के ऐसे जाने कितने गांव हैं, जहां लोगों का पहुंचना बहुत मुश्किल है. इन इलाकों में दोनों समुदाय के लोग अब भी एक-दूसरे के खून के प्यासे हैं. हालात इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि यह बता पाना बहुत कठिन हो गया है कि इसके लिए मैतेई और कुकी में से कौन सा समुदाय सीधे तौर पर दोषी है. दोनों ही समुदाय एक-दूसरे को मणिपुर के इतिहास में दर्ज हो चुके इस काले अध्याय के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. हमले की आशंका से पहाड़ों, जंगलों में रह रहे लोग अपने स्वाभाविक जीवन में लौटने को लेकर बेहद चिंतित हैं.

मणिपुर में हिंसा की आग की लपटें इतनी तेजी से फैलीं कि कई लोगों को घर से मात्र अपने तन के कपड़ों में ही भागना पड़ा. करीब तीन महीने से कैंपों में घुटन भरी जिंदगी जी रहे लोग अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं. शिविरों तक खाद्य सामग्री पहुंचाना जंग जीतने जैसा हो गया है. खाद्य सामग्री से भरे वाहनों को रास्ते में रोका और लूटा जा रहा है. कैंप में लोगों के पास खाना पहुंचा पाना प्रशासन के बूते की बात नहीं रह गई है. जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री भी ठीक से नहीं मिल पा रही. शरणार्थी शिविरों के एक-एक कमरे में कई-कई लोग रहने को मजबूर हैं. महिलाओं की स्थिति बदतर है. उनकी निजता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है. ऐसे परिवेश में गर्भवती महिलाएं दर्दनाक प्रसव के लिए मजबूर हैं. मानसून के इस मौसम में बीमारी तेजी से फैल रही है. किसी एक के बीमार होने पर पूरे कैंप के लोग, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे संक्रमित हो जा रहे हैं. डॉक्टर और दवा का मिलना तो जैसे किस्मत की बात हो गई है.

जेईई और नीट प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए

सरकार ने उठाया बेहतरीन कदम, मिलेगी ऑनलाईन कोचिंग

> राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जेईई और नीट प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाईन कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री मोहन मरकाम की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम संस्थान समिति 'संचालक मण्डल' की बैठक में इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बैठक में एकलव्य विद्यालय के प्राचार्य एवं स्टाफ का राज्य समिति के अनुमोदन से ही स्थानांतरण करने पर सहमति दी गई।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यदि विद्यालय विषय-विशेषज्ञ पर्याप्त संख्या में नहीं है, तो नियमानुसार अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। इन स्कूलों का परीक्षा परिणाम बेहतर करने के लिए शिक्षकों की क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाए और समय-समय पर विद्यालयों के अध्ययन-अध्यापन की समीक्षा भी की जाए।

बैठक में बताया गया कि शिक्षण सत्र 2023-24 में 25 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 12वीं कक्षाएं संचालित है। कक्षा 12वीं में अध्ययनरत 1474 विद्यार्थियों में से कक्षा 12वीं में जीव-विज्ञान के लगभग 982 विद्यार्थियों और गणित संकाय के लगभग 492 अध्ययनरत विद्यार्थियों को जेईई और नीट की प्रवेश परीक्षा की तैयारियों हेतु ऐसे विद्यालय जहां हाई स्पीड इंटरनेट स्थापित है, वहां ऑनलाईन कोचिंग दी जाएगी।

वर्तमान में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 22860 विद्यार्थियों के लिए गणवेश की आवश्यकता है। शाला गणवेश के लिए केव्हीआईसी के स्थान पर राज्य के स्थानीय बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए हाथकरघा विकास विपणन संघ मर्यादित रायपुर को कार्यादेश दिए जाने के प्रस्ताव को कार्योत्तर अनुमोदन दिया गया। इसके साथ ही एकलव्य विद्यालय के विद्यार्थियों को शिक्षण सत्र 2023-24 में प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिए जाने का भी अनुमोदन किया गया।

अंबानी की कंपनी विदेशी बैंकों से लेगी 1.5 अरब डॉलर का कर्ज

> रायपुर. जियो को लेकर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की योजना और फंड जुटाने की लगती दिख रही है. इसी वजह से कंपनी ने विदेशी बैंकों से संपर्क किया है. ET की रिपोर्ट के मुताबिक, रिलायंस जियो इस फंड का इस्तेमाल 5G नेटवर्क को लेकर करेगा. रिलायंस जियो की इस साल की शुरुआत तक 5जी नेटवर्क पर ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करने की योजना है.

रायपुर. जियो को लेकर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की योजना और फंड जुटाने की लगती दिख रही है. इसी वजह से कंपनी ने विदेशी बैंकों से संपर्क किया है. ET की रिपोर्ट के मुताबिक, रिलायंस जियो इस फंड का इस्तेमाल 5G नेटवर्क को लेकर करेगा. रिलायंस जियो की इस साल की शुरुआत तक 5जी नेटवर्क पर ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करने की योजना है.

भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने कर्ज लेने के लिए वैश्विक बैंकों से संपर्क किया है. कंपनी करीब 1-1.5 अरब डॉलर का कर्ज जुटाएगी. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस लोन का इस्तेमाल 5G नेटवर्क गियर खरीदने के अलावा कई अन्य चीजों के लिए किया जाएगा.

ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, जेपी मॉर्गन चेज, सिटी, एचएसबीसी और अन्य जैसे वैश्विक ऋणदाता Jio के लिए लगभग 3-5 वर्षों के लिए ऋण की व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं, जिसकी लागत सुरक्षित ओवरनाइट फाइनेंसिंग दर (SOFR) से अधिक होने की संभावना है. ऋण की कीमत SOFR से लगभग 100 से 150 अंक अधिक हो सकती है. इसके अलावा यूरोपियन एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी फिनवेरा जियो को ऑफशोर लोन देने के लिए कर्जदाताओं को गारंटी जारी कर सकती है.

5G को लेकर Jio का क्या है प्लान?

अंबानी की Jio पिछले अक्टूबर से तेजी से अपने 5G कवरेज का विस्तार कर रही है. टेलीकॉम ऑपरेटर पहले ही देश के लगभग 5,700 शहरों और कस्बों में 5G सेवाएं शुरू कर चुका है. जियो का कहना है कि वह 25 अरब डॉलर का संचयी 5जी निवेश करेगा, जिसमें 11 अरब डॉलर के 5जी स्पेक्ट्रम हासिल करने की लागत भी शामिल है. Jio एकमात्र भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर है जिसने भारत की 5G स्पेक्ट्रम नीलामी मे 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए आवेदन किया है.

जियो एरिक्सन और नोकिया के साथ काम कर रहा है

Jio अपने 5G के लिए यूरोपीय नेटवर्क विक्रेता एरिक्सन और नोकिया के साथ काम कर रहा है. टेलीकॉम ऑपरेटर ने नोकिया से उपकरण खरीदने के लिए 1.6 बिलियन डॉलर जुटाने की इच्छा भी व्यक्त की है. गौरतलब है कि नोकिया ने पिछले अक्टूबर में घोषणा की थी कि उसने भारत में 5G रोलआउट के लिए Jio को उपकरण आपूर्ति करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. रिलायंस जियो ने एयरवेव्स हासिल करने के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया है. इसके साथ ही अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत में 5जी ऑफर करने वाली पहली कंपनी बन गई है.

जेटीएल इंडस्ट्री के शेयर ने निवेशकों को किया मालामाल

“रायपुर. भारतीय शेयर बाजार ने पिछले कुछ सालों में कई मल्टीबैगर शेयर दिए हैं. इन शेयरों ने अपने निवेशकों को खूब पैसा कमाया है. आज हम जिस शेयर के बारे में बताने जा रहे हैं, 3 साल पहले इसकी कीमत महज 15 रुपये हुआ करती थी, लेकिन अब इसका एक शेयर 350 रुपये से भी ज्यादा में मिलता है.”

बोनस शेयर मिलेंगे

आज हम आपको जेटीएल इंडस्ट्रीज के बारे में बताने जा रहे हैं. इस शेयर ने कोविड के बाद के दौर में जबरदस्त तेजी दिखाई है. पिछले 3 साल के दौरान इसकी कीमत में 2,300 फीसदी का इजाफा हुआ है. अब यह कंपनी अपने शेयरधारकों को एक और बड़ा तोहफा देने जा रही है. कंपनी जल्द ही अपने शेयरधारकों के लिए बोनस जारी कर सकती है.

महीने के अंत में बैठक

जेटीएल इंडस्ट्रीज ने बताया है कि उसके निदेशक मंडल की बैठक (JTL इंडस्ट्रीज बोर्ड मीटिंग) इस महीने के अंत में होने वाली है. 29 जुलाई 2023 को होने वाली बैठक में जेटीएल इंडस्ट्रीज का बोर्ड बोनस शेयरों के मुद्दे पर विचार करेगा और इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी देगा. बोर्ड की मंजूरी के बाद प्रस्ताव पर शेयरधारकों की मंजूरी ली जाएगी. इसके बाद मौजूदा नियमों के मुताबिक पात्र शेयरधारकों को बोनस शेयरों का लाभ मिलेगा.

इस प्रकार गति आई

अब तक के प्रदर्शन को देखें तो इस स्मॉलकैप स्टॉक ने अपने निवेशकों को खूब पैसा कमाया है. पिछले एक महीने में इसकी कीमत में करीब 9 फीसदी का इजाफा हुआ है, जबकि पिछले 6 महीने के दौरान इसकी कीमत में करीब 15 फीसदी का इजाफा देखने को मिला है. पिछले 1 साल में यह करीब 70 फीसदी चढ़ा है, जबकि पिछले 3 साल में इसने 15 रुपये से 360 रुपये तक का सफर तय किया है.

4 हजार बने 1 लाख

इसके मुताबिक, अगर किसी निवेशक ने 3 साल पहले जेटीएल इंडस्ट्रीज के शेयरों में सिर्फ 4000 रुपये का निवेश किया होता तो आज उसे करीब 1 लाख रुपये मिलते.

पेड़ों को भी मिलेगी पेंशन जानिए कैसे करें आवेदन

रायपुर. हम इंसान अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए कई तरह के बीमा लेते हैं. सरकार लोगों को विभिन्न प्रकार की पेंशन सुविधाएं भी प्रदान करती है. अब सरकार पेड़ों का बीमा भी कर रही है. हरियाणा सरकार ने पेड़ों को पेंशन देने की नई योजना शुरू की है. इसका नाम प्राण वायु देवता योजना है. हम आपको इस लेख में इस योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे.

अगर आपके पास भी 75 साल से ज्यादा पुराना पेड़ है तो आपको भी हर महीने 2,500 रुपये की पेंशन दी जाएगी. यह राशि पेड़ की देखभाल करने वाले के खाते में जायेगी. पेड़ों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई तरह के कानून बनाए हैं. पेड़ों के संरक्षण के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं. अगर आप भी हरियाणा सरकार की इस योजना में आवेदन करते हैं तो आप भी कमाई कर सकते हैं. सरकार ने इस योजना की घोषणा 2021 में ही कर दी थी. सरकार का इस योजना को लाने के पीछे का मकसद पेड़ों की कटाई को रोकना और हवा की गुणवत्ता में सुधार करना है.

किस पेड़ से मिलेगी पेंशन

हरियाणा सरकार का कहना है कि इस योजना में 75 साल या उससे अधिक उम्र के पेड़ों को शामिल किया गया है. इसका मतलब यह है कि अगर आपके घर के आंगन में कोई पेड़ 75 साल से ज्यादा पुराना है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस योजना का लाभ छोटे किसानों और गरीब मजदूरों को भी मिलता है. इसके पीछे उद्देश्य यह है कि इस तरह वह अपने खाली समय में पेड़ों की देखभाल करेंगे. इस तरह वह पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ कुछ पैसे भी कमा लेंगे. हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवर पाल ने बताया कि वह हर साल वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना को बढ़ाते हैं, उसी तरह इस योजना को भी बढ़ाएंगे.

आपको बता दें कि गिरे हुए पेड़, खोखले, मृत, सूखे और रोगग्रस्त पेड़ इस योजना में शामिल नहीं होंगे. इसका मतलब यह है कि इस योजना में केवल उन्हीं पेड़ों को शामिल किया गया है जो जमीन पर खड़े होंगे.

इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

अगर आप भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड होना जरूरी है. आवेदन के समय आपको निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा. आप इस योजना में आधार से लिंक मोबाइल नंबर ही दें.

कहां आवेदन करें

इस योजना के लिए आपको नजदीकी वन विभाग कार्यालय में जाना होगा. यहां आपको कृषि अधिकारी से संपर्क करना होगा. वे आपको इस योजना से संबंधित एक फॉर्म देंगे, आपको वह फॉर्म भरना होगा.

एक ऐसा समाज जो अपने हितों से उठकर मानवता के लिए काम करता हैः डॉ. मनोज अग्रवाल

प्रिय पाठकों आज पूरे विश्व में अग्रवाल समाज ने अपने जनसेवा की कार्यों से अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित की है तथा आज पूरे विश्व में अग्रवाल समुदाय आज भी सेवा कार्यों में जुटा हुआ है। आज में डॉ. मनोज अग्रवाल बेहद हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि, हम उनका उल्लेख करने जा रहे है, जिन्होंनें समाज के उधार और उनती के लिए क्षत्रिय वर्ण छोड़कर वैश्य धर्म अपनाया था। राम के पुत्र कुश की 34वीं पीढ़ी संतान महाराजा अग्रसेन की।

साथियों मानव जीवन पांच तत्वों का पुतला है। उसका नाम मनुष्य है। लेकिन जीवन जीने की कला के अभाव में उसका जीवन व्यर्थ हो गया है। इंसान में मानवता का गुण नहीं है तो उसे जीवन जीने की कला का ज्ञान भी नहीं हो सकता। आज की सदी में जीवन का उद्देश्य भावनाओं से जुड़ा है। यदि हम और आप एक दूसरे के प्रति प्रेम, उदारता, सहयोग की भावना नहीं है तो वह मानव जीवन के समान नहीं है, जो अपने कार्यो से दूसरों को कष्ट पहुंचाता है।

प्रियजनों भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए इंसान अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन जब वे इस दुनिया से विदा होता हैं तो वे अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा पाता। उनकी सारी कमाई यहीं रह जाती है। अगर वे कोई चीज अपने साथ ले जाते हैं तो वह है उनके अच्छे कर्म और लोगों की दुआएं होती है। हमारे शास्त्रों और ग्रंथो में धर्म के अनेक लक्षण बताये गए हैं उन्ही में से एक लक्षण है मानवता यानि मानव मात्र के कल्याण के लिये किया गया कार्य।

बीतते समय के साथ मनुष्य के विकास का सामाजिक दायरा बढ़ा, सोच बढ़ी, जिसके साथ-साथ नैतिकता बढ़ी। आज पारिवारिक मूल्यों की बात हो, पर्वजोक दीज निवाली आदर सम्मान की बात हो तो सर्वप्रथम हमारा अग्रवाल समाज आता है। जिसके लिए मानवता की सेवा करना और समाज को आगे ले जाना कर्तव्य के रूप में देखा जाता है।

मौजूदा समय में कुछ लोग या समाज ऐसे होते हैं जो अपने अतीत के गौरव को गाकर अपना गुनआन करते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने वर्तमान पर जिंदा रहते हैं। किंतु हमारा अग्रवाल समुदाय देश का ऐसा समाज है जिसका अतीत भी गौरवशाली रहा है और वर्तमान भी देश में अपना एक विशेष स्थान बनाये हुए है। यह सब हमारे आराध्य महाराजा अग्रसेन की शिक्षाओं व उनके आशीर्वाद का ही परिणाम है कि आज देश में अग्रवाल समाज का विशेष स्थान है।

इस समाज के प्रवर्तक अग्रोहा राज्य से संस्थापक महाराजा अग्रसेन हुए, जिन्होंने एक मुद्रा-एक ईंट जैसी आदर्श पद्धति का प्रचलन कर समाजवाद का सही रूप और गरीबी हटाओं का नारा सार्थक कर दिखाया था। उनका राज्य सच्चे अर्थों में समाजवाद,आधुनिक युग में सहकारिता, सर्वोदय, अर्थदान, भू-दान व सम्पत्ति दान इत्यादि लोकतंत्र, निर्धनता उन्मूलन जैसी प्रवृत्तियों का साकार प्रतीक था। उन्होंने 18 गणों की सम्पति से राज्य चला कर एकतंत्र में लोकतंत्र की नींव रखी। आज हम जिन स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे, परस्पर सहयोग, स्वावलम्बन, स्वदेशी की भावना, सर्वधर्म समभाव, परिश्रम, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा आदि आदर्शों की बात करते हैं, वे सब महाराजा अग्रसेन के राज्य में 5100 वर्ष पूर्व विद्यमान थे।

बंधुओ महाराजा अग्रसेन के चार गुण सत्य, अहिंसा, समानता एवं अपनत्व तथा चार सिद्धांत-दुष्टों का दमन, साधुओं का संरक्षण, गरीबी का तर्पण व शोषकों का क्षरण को अग्रवाल समाज ने आज भी अपना रखा है और इसी कारण यह समाज देश में अग्रणी बना हुआ है।

सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं से ग्रामीणों को हो रहा लाभ...

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली की खण्डपीठ द्वारा जिले के अत्यंत सुदूर ब्लॉक उसूर के आवापल्ली स्थित पोटाकेबिन में बाल अधिकार सम्बन्धी प्रकरणों के निराकरण हेतु शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य सोनल कुमार गुप्ता ने आवेदकों से रूबरू होकर बाल अधिकारों से सम्बंधित समस्याओं को सुना और प्रकरणों के निराकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही की।

आयोग द्वारा इस दौरान 300 से अधिक प्रकरण प्राप्त हुए ज्यादातर आवेदन आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड बनाने के मिले आवेदन के निराकरण एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया। शिविर मे लाभान्वित होने सुदूर और अंदरुनी गांवों की विशाल जनसंख्या शामिल हुए।

प्रकरणों की सुनवाई के दौरान आयोग के सदस्य सोनल कुमार गुप्ता ने बच्चों के माता पिता से उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और आजिविका के बारे मे जानकारी लेते हुए राष्ट्रीय आजिविका मिशन, शिक्षादूत, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका जैसे पदो पर नियमानुसार नियुक्ति प्रदान कर पात्र हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।

रेसिंग की दुनिया में बादशाहत हासिल करने आ रही BMW M 1000 RR 306 kmph है टॉप स्पीड

> "BMW Motorrad ने भारत में M 1000 RR को 49 लाख रुपये एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. ब्रांड ने 55 लाख रुपये एक्स-शोरूम कीमत पर मोटरसाइकिल का Competition वर्जन भी लॉन्च किया है. कंपनी इन दोनों मोटरसाइकिलों की बुकिंग ले रही है. M 1000 RR मोटरसाइकिल,S 1000 RR का ट्रैक पर फोकस करने वाला वर्जन है और 'एम' बैज के साथ आने वाली पहली प्रोडक्शन सुपरबाइक भी है."

टीजर इमेज हुआ जारी

BMW Motorrad इंडिया में हाइ-स्पेक एम 1000 आरआर के लॉन्च के लिए तैयारी कर रहा है, क्योंकि ब्रांड ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक टीजर इमेज पोस्ट की है. स्टैंडर्ड एस 1000 आरआर के आधार पर, जिसकी कीमत वर्तमान में 20.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, एम वेरिएंट अधिक फीचर्स, हल्के कंपोनेंट और भारी कीमत के साथ आएगा. अन्य वेरिएंट की कंपैरिजन में एम वेरिएंट की कीमत अधिक है. इससे पहले वाले एम वेरिएंट की कीमत 45 लाख रुपये के आस-पास थी, इसलिए कयास लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत 45 लाख रुपये से अधिक हो सकती है.

कैसी होगी डिजाइन?

टीजर इमेज में इसकी तस्वीरें उतना क्लियर नहीं है, लेकिन एम 1000 आरआर में एक नया डिजाइन किया गया टेल सेक्शन दिया जा सकता है, जो एक छोटी नंबर प्लेट धारक और एक एम एंड्योरेंस सीट के साथ कॉम्पैक्ट और हल्का होगा.

3.1 सेकंड में 0-100 किमी /घंटा

बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने इन दोनों बाइक्स के साथ नई डिजाइन के विंगलेट्स लगाए हैं जो कार्बन फाइबर के बने हैं. ये बाइक के डाउनफोर्स को बढ़ाने में काफी मददगार हैं. दोनों में 999 सीसी का चार-सिलेंडर इंजन लगाया गया है जो वाटर/ऑयल कूल्ड तकनीक वाला है. ये इंजन 209 बीएचपी ताकत और 113 एनएम पीक टॉक बनाता है जिसे कंपनी ने 6-स्पीड गियरबॉक्स से लैस किया है. सिर्फ 3.1 सेकंड में ही ये बाइक 0-100 किमी/घंटा रफ्तार पकड़ लेती है, वहीं इसकी टॉप स्पीड 306 किमी/घंटा है

ADAS सेफ्टी फीचर्स से लैस हैं ये टॉप 5 शानदार कारें

महंगी गाड़ियों वाली आती है फील, देखें लिस्ट

ADAS (एडीएएस) या एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम वाहन उद्योग की नई चर्चा बन गई है. आखिर एडीएएस एक आकर्षक फीचर कैसे बन गया है. दरअसल यह सेफ्टी फीचर्स का एक सेट है जो ड्राइवर को सड़क पर किसी भी बाधा से बेहतर ढंग से निपटने में मदद करता है. यह कार के साथ-साथ सड़क पर ड्राइवर और यात्रियों के लिए ज्यादा सुरक्षा सुनिश्चित करता है. यह सेफ्टी सूइट एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे फीचर्स के साथ आता है. यहां हम आपको बता रहे भारत की टॉप-5 सबसे किफायती कारें जो ADAS फीचर्स के साथ आती हैं.

एमजी एस्टर

MG Astor भारत की सबसे बेहतरीन ADAS कारों में से एक है, जो अपने सेगमेंट में काफी पॉपुलर है. इस कार में लेवल 2 ADAS सिस्टम मिलता है, जिसमें ढेर सारे फीचर्स दिए गए हैं. इसके फीचर्स को देखते हुए ग्राहक इस कार को बहुत पसंद करते हैं. इस कार के एडवांस ड्राइविंग एसिस्ट सिस्टम में एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट, लेन डिपार्चर अलार्म, लेन डिपार्चर मिटिगेशन, ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक असिस्ट, फ्रंटल कोलिशन अलार्म, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, हाई बीम असिस्ट और स्पीड असिस्ट सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं.

महिंद्रा एक्सयूवी 700

महिंद्रा एक्सयूवी 700 भी भारत की सबसे सुरक्षित कारों में से एक है. महिंद्रा ने एक्सयूवी 700 में एडीएएस लेवल 2 के फीचर्स से लैस किया है. यह वर्तमान में भारत में सबसे अच्छी ADAS सिस्टम वाली कारों में से एक है. महिंद्रा एक्सयूवी 700 के एडीएएस सिस्टम में फ्रंट कोलिशन अलर्ट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीपिंग असिस्ट, लेन डिपार्चर अलार्म, लेन डिपार्चर मिटिगेशन, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, स्मार्ट पायलट एसिस्ट और हाई बीम असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं.

होंडा सिटी हाइब्रिड

Honda City Hybrid को सबसे पहले कैमरा-आधारित ADAS सुइट मिला. इसकी कीमत 18,89,000 रुपये से शुरू होती है. इसमें लेन कीप असिस्ट, कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग, रोड डिपार्चर मिटिगेशन, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो हेडलैंप बीम एडजस्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं. फेसलिफ्ट के बाद, पेट्रोल वैरिएंट – V, VX और ZX Hkh ADAS के साथ आते हैं. होंडा सिटी 5वीं पीढ़ी की कीमत 11,57,000 रुपये से शुरू होती है. होंडा सिटी में ADAS सुइट को 'होंडा सेंसिंग' कहा जाता है.

हुंडई वरना

Hyundai Verna होंडा सिटी के नक्शेकदम पर चलते हुए एडीएएस की पेशकश करने वाली देश की दूसरी मिड-साइज सेडान बन गई. हुंडई वरना में यह सुरक्षा सूइट, जिसे हुंडई स्मार्टसेंस कहा जाता है, एसएक्स (ओ) ट्रिम पर उपलब्ध है, जिसकी कीमत 14.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ब्लाइंड-स्पॉट कोलिजन वार्निंग, लेन कीपिंग असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, स्टॉप एंड गो के साथ स्मार्ट क्रूज कंट्रोल और लेन फॉलोइंग असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं.

टाटा हैरियर

Tata Harrier की कीमत ₹ 15.00 लाख और ₹ 24.00 लाख के बीच है. अपडेट मॉडल में कई ADAS हाइलाइट्स शामिल हैं, जिनमें फॉरवर्ड कोलिशन वार्निंग, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन चेंज अलर्ट, हाई बीम असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और रियर कोलिशन वार्निंग शामिल हैं

लॉन्च से पहले ग्लोबल वेबसाइट पर पेश हुई Redmi Watch 3 Active

वॉच के प्रोडक्ट पेज से पता चलता है कि रेडमी वॉच 3 एक्टिव को दो कलर ऑप्शंस-ब्लैक और ग्रे में लाया जाएगा. यूजर ग्रीन और येलो स्ट्रैप्स को अलग से भी खरीद पाएंगे. शाओमी ने इस वॉच की कीमत का खुलासा अभी नहीं किया है.

Redmi Watch 3 Active के स्पेसिफिकेशन

रेडमी वॉच 3 एक्टिव में 1.83 इंच एलसीडी डिस्प्ले मिलेगा, जो (240×280 पिक्सल) रिजॉल्यूशन और 450 निट्स तक एडजस्टेबल ब्राइटनेस के साथ आएगा. रेडमी वॉच 3 एक्टिव में ब्लूटूथ कॉलिंग का भी सपोर्ट मिलेगा. वॉच में 100 से अधिक स्पोर्ट्स मोड मिलेंगे, जिसमें आउटडोर रनिंग, ट्रेडमिल, आउटडोर साइक्लिंग, वॉकिंग, ट्रैकिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं.

इसके अलावा वॉच में ब्लड ऑक्सीजन लेवल सेंसर और हार्ट रेट मॉनिटर जैसे कई हेल्थ मॉनिटर भी मिलेंगे. रेडमी वॉच 3 एक्टिव स्लीप मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी के साथ आएगी. Redmi Watch 3 Active की बैटरी क्षमता की बात करें तो इसके साथ 289mAh की बैटरी मिलेगी.

> Redmi Watch 3 Active को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी है. कंपनी ने अपनी इस स्मार्टवॉच को ग्लोबली अनवील कर दिया है. कंपनी के मुताबिक इस स्मार्टवॉच में 1.83 इंच का आयताकार एलसीडी डिस्प्ले होगा जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 240×280 पिक्सल होने वाला है. ये ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी सपोर्ट और कई हेल्थ सूट और वॉच फेस के साथ आएगी.

बैटरी बैकअप को लेकर कंपनी का दावा है वॉच को सामान्य उपयोग के साथ 12 दिनों तक और अधिक इस्तेमाल के साथ आठ दिनों तक चलाया जा सकता है. वॉच मैग्नेटिक चार्जर को सपोर्ट करेगी. Redmi Watch 3 Active में वॉटर रेसिस्टेंट के लिए 5 ATM रेटिंग, माइक्रोफोन और स्पीकर का भी सपोर्ट मिलेगा.

15 अगस्त को नहीं आ रही है Mahindra Thar 5 Door

5 दरवाजों वाली महिंद्रा थार लॉन्च डेट को लेकर बीते दो दिनों से काफी माहौल बना हुआ है और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं कि महिंद्रा अपनी 5 डोर थार को आगामी 15 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका में अनवील करने वाली है. अब इन तमाम खबरों का महिंद्रा ऑटोमोटिव ने खंडन करते हुए इंस्टाग्राम पोस्ट किया है. कंपनी ने साफ तौर पर कहा है कि महिंद्रा थार 5 डोर इस साल नहीं आ रही है, ऐसे में 15 अगस्त को इसकी लॉन्चिंग का सवाल ही नहीं है. महिंद्रा ने स्पष्ट किया कि हम पहले ही बता चुके हैं कि 5 दरवाजों वाली थार अगले साल लॉन्च होगी.

भारत के अलावा साउथ अफ्रीका भी महिंद्रा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण बाजार है. कंपनी साउथ अफ्रीका के मार्केट में साल 1996 से वाहनों की बिक्री कर रही है, बताया जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ और मॉडल जैसे एक्सयूवी 300, एक्सयूवी 700 और स्कार्पियो-एन को भी वहां पर पेश किए जाने की योजना है. हालांकि भारत में Mahindra Thar 5 - Door की बिक्री के लिए ग्राहकों को थोड़ा इंतजार करना होगा. अब कंपनी ने साफ कर दिया है कि साउथ अफ्रीका में भी Mahindra Thar 5 - Door अगले साल ही लॉन्च होगी.

Mahindra Thar 5 - Door की डिजाइन और विशेषताए

रिपोर्ट की मानें तो महिंद्रा की 5 दरवाजे वाली Thar, जिमनी 5-दरवाजे वाले एडिशन की तुलना में काफी बड़ी होगी. 5-दरवाजे वाली जेंत एडिशन का एनालिसिस करने पर यह पता चलता है कि इसमें पांच सीट की व्यवस्था होगी. हाल ही में लीक हुई एक रिपोर्ट की मानें तो यह तीन सीटों के साथ आ सकती है. एक और टेस्ट म्यूल, जिसे टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, बताता है कि आने वाली 5-दरवाजे वाली SUV को सनरूफ से लैस रखा जाएगा. इसमें एक सिंगल-पैन इलेक्ट्रिक sunroof मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा, SUV में लंबी व्हीलबेस और दो अतिरिक्त दरवाजे होंगे. बाकी और विशेषताएं मौजूदा एडिशन के थर की तरह ही रहेंगी.

Jimny को मिलेगी कड़ी टक्कर

बतौर ऑफरोडिंग लाइफस्टाइल व्हीकल महिंद्रा थार सीधे तौर पर मारुति जिम्नी को टक्कर देगी, जिसे हाल ही में 12.74 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में पेश किया गया है. हालांकि जिम्नी केवल एक 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन विकल्प के साथ ही आती है, वहीं थार में ग्राहकों को मल्टीपल इंजन ऑप्शन चुनने का मौका मिलेगा. इसके अलावा थार का इंजन ज्यादा बड़ा और पावरफुल भी है. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि महिंद्रा थार 5-डोर को किस कीमत में लॉन्च किया जाएगा.

चिरायु योजना से अलीना को मिला जीवनदान, परिवार ने CM बघेल का जताया आभार

> पिछले साल की बात है, अलीना नाम की एक छोटी बच्ची अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना कर रही थी. महासमुंद के ग्राम तेन्दुवाही के आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों में वह सबसे कमजोर थी और किसी भी काम या खेल में जल्द थक जाती थी. थकान ने उसे स्वाभाविक जीवन से दूर कर दिया था. उसकी सेहत भी धीरे-धीरे खराब हो रही थी, जिससे परिवार में भी तनाव बढ़ रहा था.

अभिभावकों ने अलीना का कई जगह इलाज कराया, लेकिन उसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं आया. एक दिन चिरायु टीम ग्राम तेन्दुवाही के आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करने पहुंची. इससे नन्हीं अलीना का जीवन ही बदल गया. आज वह स्वस्थ है और थकान भरे जीवन से मुक्ति पा चुकी है. परीक्षण के बाद टीम ने संभावना व्यक्त किया कि बालिका अलीना पटेल हृदय रोग से पीड़ित हो सकती है. बालिका अलीना के माता-पिता से चर्चा में उन्हें पता चला कि, बच्ची जन्म से ही अत्यंत दुर्बल है. वह खेलने, चलने में थोड़े समय पर ही थक जाती है.

खान-पान में भी अरूचि दिखाती है. अलीना का शारीरिक विकास भी अन्य बच्चों की तुलना में बहुत कम पाया गया. चिरायु टीम द्वारा अलीना को जिला अस्पताल महासमुन्द लाकर नये सिरे से स्वास्थ्य की गहन जांच की गई. जांच में पाया गया कि वह हृदय रोग से पीड़ित है और उसकी तुरंत सर्जरी किया जाना जरूरी है, इससे बच्ची के माता-पिता घबरा गए.

चिरायु टीम ने बच्ची अलीना के माता-पिता को चिरायु योजना एवं नि:शुल्क सर्जरी के बारे में विस्तार से जानकारी दी. बच्ची को ऑपरेशन के लिए रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा अलीना की सफल सर्जरी की गई. उसकी सेहत बहुत सुधर गई और अब वह बच्चों के साथ खेल भी सकती है. उसके परिवार में खुशियां वापस आ गई और उसके चेहरे पर मुस्कान फिर से लौट आई.

चिरायु योजना ने अलीना को नया जीवन दिया. अलीना के माता पिता ने सहयोग और बेहतर इलाज के लिए राज्य सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद देते हुए कहा कि चिरायु योजना से मेरी बेटी को नई जिंदगी मिली है.

दुग्ध कारोबार से किसानों-पशुपालकों के जीवन में आई समृद्धि, रोजगार के साथ खुले आमदनी के रास्ते

दुग्ध के कारोबार से किसानों-पशुपालकों के जीवन में समृद्धि की नदी बहने लगी है. सुकमा में 50 से ज्यादा पशुपालकों की को-ऑपरेटिव सोसायटी ने 20 लाख रुपये तक के दूध का कारोबार कर डाला है. जिसका आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. रोजगार उपलब्ध कराने के मकसद से सरकार की ओर से स्थापित किया गया शबरी दुग्ध सागर केंद्र अब नए कीर्तिमान बना रहा है. इसकी शुरुआत 45 पशुपालक और किसानों का समूह बनाकर की गई थी. जो बढ़कर अब 50 से ज्यादा हो गई है. इन्हें प्रत्यक्ष रूप से फायदा हो रहा है.

जब कि इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों को रोजगार उपलब्ध होने से उनकी कमाई के रास्ते खुल गए हैं.

सरकार द्वारा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दुध उत्पादन सहकारी समिति का गठन किया गया है. डेयरी का सफल संचालन सामूहिक रूप से किया जा रहा है. जिससे जिले में उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है. साथ ही लोगों को पौष्टिक स्वास्थ्यवर्धक ताजा शुद्ध दूध उपलब्ध हो रहा है. समिति के अध्यक्ष रामाराजू ने बताया कि दुग्ध कारोबार को शुरू करने के कुछ महीने याद ही आय का आंकड़ा 20 लाख रुपये के पार पहुंच चुका है. अब तक 35 हजार लीटर से ज्यादा दूध किसानों से खरीदकर इसके उत्पाद तैयार किए गए हैं. औसतन हर दिन 700 लीटर दूध तक का कारोबार हो रहा है,जिसमें वृद्धि हो रही है.

इसे एक को-ऑपरेटिव मॉडल के तौर पर तैयार किया गया है. पशुपालकों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इसके संचालन की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है. सालभर बाद कमाई को इकट्ठा कर इसका एक हिस्सा संधारण में खर्च किया जाएगा. राज्य शासन की ओर से मशीनें स्थापित की गई है. मशीनों से शुद्धता की परख के बाद गुणवत्ता के साथ निर्धारित दर पर दूध का क्रय किया जाता है. इसके बाद मशीनों के माध्यम से दूध का निर्माण सह पैकेजिंग की जाती है. संचालन समिति के माध्यम से केंद्र में बने शुद्ध पौष्टिक स्वास्थ्यवर्धक दूध के उत्पाद जिलेवासियों के अलावा जिले में स्थित कैंप और शिक्षण संस्थानों में आवश्यकता अनुरूप उपलब्ध कराया जाता है. डेयरी के सुचारू रूप से संचालन के लिए सी-मार्ट के पास शबरी दुग्ध सागर दुकान भी शुरू की जा रही है. शबरी दुग्ध डेयरी में दूध के साथ दही, खोवा और पनीर का भी विक्रय शुरू किया गया है. घी, खांबा और पनीर को बनाने में इसकी गुणवता पर और डेयरी में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है. पैकिंग पहले ही मशीन की अच्छे तरीके से सफाई की जाती है. किसानों द्वारा दूध लाने के बाद उसकी लेक्टरोमशीन से गुणवत्ता की जांच की जाती है फिर दूध फिल्टर कर सीधा बिलर मशीन में जाता है. जहां मशीन द्वारा पैकिंग की जाती है. फिर दूध पैकेट को इकट्ठा कर मार्केट में भेज दिया जाता है.

मछली पालन से बदली तकदीर और तस्वीरः कोसगाई दाई मछुआ सहकारी समिति की बढ़ी आमदनी

फीचर स्टोरी। ये मेहनतकश और सरकार की सफल योजनाओं की तस्वीर है, जो खुशहाली की कहानी बयां कर रही है. ये हाथों में जाल और जाल में मंछलियां कोसगाई दाई मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों की तकदीर बदल रही हैं. यूं कहें कि सरकार की योजनाओं से जुड़कर खुद की किस्मत को उकेर रही हैं. भूपेश सरकार की ये योजनाएं गांव-गांव खुशहाली, उन्नति और मछली पालकों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर रही हैं. मछली पालकों की आमदनी में इजाफा को रफ्तार मिल रही है.

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित योजनाओं से लाभ उठाकर मछली पालन का कार्य करने वाले मछुआ सहकारी समिति के सदस्य आर्थिक संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं. स्वयं आत्मनिर्भर हो रहे हैं और अन्य लोगों को भी इस कार्य से रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं. जिले के कटघोरा विकासखण्ड के ग्राम छुरीकला के कोसगाई दाई मछुआ सहकारी समिति विभागीय योजनाओं से जुड़कर मछली पालन का कार्य कर रहे हैं. समिति के सदस्य मछली पालन को अपने आय का प्रमुख जरिया बनाया है. समिति के सदस्यों ने सफलता प्राप्त की ही नहीं, बल्कि अब वे अपने इस काम को नई ऊंचाईयां दे रही है. समिति के सदस्यों द्वारा कृषि कार्य के साथ - साथ मछली पालन का व्यवसाय भी किया जा रहा है. उन्हें मछली पालन विभाग द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देकर मछली पालन के लिए प्रेरित किया गया, जिससे समिति के सदस्य इस कार्य में संलग्न होकर छुरी के भेलवाडबरा सिंचाई जलाशय को पट्टे पर लेकर मत्स्य पालन का कार्य प्रारंभ किया. समिति द्वारा जलाशय में रोहू, कतला, मिरगल, ग्रासकार्प जैसे अन्य मछली बीज का संचयन किया गया है. दाई महुआ सहकारी समिति के अध्यक्ष आत्माराम केंवट ने बताया कि मत्स्य पालन कार्य से जुड़कर समिति के सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, इससे उन्हें आमदनी का अतिरिक्त साधन प्राप्त हुआ है. उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा उन्हें योजना के तहत 3 लाख का अनुदान एवं सहायक सामग्री के रूप में मत्स्य बीज अंगुलिका, चटजाल, आईस बॉक्स इत्यादि सामग्री भी उपलब्ध कराया गया है.

साथ ही उन्हें समय-समय पर आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया. समिति के सदस्य मत्स्य बीज एवं जाल पाकर काफी उत्साहित हुए और मत्स्य पालन के प्रति रूचि लेने लगे, जिसका सकारात्मक परिणाम अब देखने को मिल रहा है. समिति द्वारा अपने दैनिक कामकाज करने के साथ-साथ मत्स्य पालन का कार्य भी जिम्मेदारी पूर्वक कर रहे हैं. उनके द्वारा जलाशय की आवश्यक साफ-सफाई, मछलियों की देख-रेख, उन्हें मत्स्य आहार देने के साथ ही नियमित रूप से जलाशय की रख-रखाव का कार्य भी किया जा रहा है. आत्माराम ने बताया कि योजना से जुड़कर अब तक 3000 किलोग्राम से अधिक का मत्स्य उत्पादन किया है जिसके विक्रय से उन्हें 3 लाख से अधिक की आमदनी हुई है. कोसगाई दाई मछुआ सहकारी समिति के सभी सदस्यों ने नियमित रूप से मछली पालन से जोड़कर रोजगार दिलाने एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु जिला प्रशासन एवं छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया है.

वनाश्रितों को मिला न्याय, वनोपज से बढ़ी आय तेंदूपत्ता संग्रहण बना आमदनी का प्रमुख जरिया

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जंगलों के बीच रहकर जीवन-यापन करने वालों के बारे में सोचा और तेंदूपते का समर्थन मूल्य बढ़ाया. आज समर्थन मूल्य पर बेचने से वनाश्रितों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ आजीविका के साधन भी बेहतर होते जा रहे हैं.

कोंडागांव के दादरगढ़ निवासी अकालू मंडावी और उनकी पत्नी बेजतीन मंडावी बताते हैं कि एक साल में एक बार तेंदूपते की तोड़ाई होती है. जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समर्थन मूल्य तय किया है, तब से हमारी कमाई दोगुनी हो गई है. अब पूरा परिवार मिलकर दिलचस्पी के साथ इस काम को करते है. तेंदूपत्ता संग्रहण से मिले पैसे से हमने टीवी खरीदने के सपने को साकार किया है और अच्छे कपड़े खरीदकर पहन पा रहे हैं.

छतीसगढ़ सरकार द्वारा तेंदूपत्ता छ संग्रहण की राशि 2500 रुपये से बढ़ाकर 4 हजार रुपये प्रति मानक बोरा किए जाने के बाद से वनांचलों में बदलाव का दौर शुरू हो गया है. संग्राहकों को 424

करोड़ 11 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि का भुगतान होने से संग्रहण को बढ़ावा मिल रहा है. हर साल संग्राहकों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है और छत्तीसगढ़ सर्वाधिक खरीदी भी कर रहा है. तेंदूपत्ते के व्यापार से महिला समूहों को भी जोड़ा जा रहा है. समूह को रोजगार भी मिल रहा है. राज्य सरकार द्वारा अच्छा दाम मिलने की वजह से जनजातीय समुदाय अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से व्यतीत कर रहे हैं और उनके रहन-सहन में भी बदलाव आने लगा है. तेंदूपत्ता संग्रहण दर में बढ़ोतरी किए जाने से खुश हैं और वे प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रहे हैं.

नारायणपुर जिले के निवासी चौतराम यादव बताते है कि जंगलों के बीच निवासरत लोगों के लिए तेंदूपत्ता ही आमदनी का बड़ा जरिया बन गया है. पत्ते की तोड़ाई से लेकर बंडल बनाने का काम परिवार के साथ मिलकर करते हैं. पहले दाम कम मिलने की वजह से आर्थिक तौर पर काफी दिक्कतें होती थीं. लेकिन अब हरा सोना कहलाने वाला तेंदूपत्ता वाकई सोने जैसा ही है.

तरक्की में अब नहीं आर्थिक बाधाः बेरोजगारी भत्ता योजना बनी वरदान, 1 लाख से अधिक युवाओं के चेहरे पर बिखरी मुस्कान

छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के भविष्य के म9ेनजर नए-नए रास्ते खोल रही है, ताकि रोजगार मिले, उनका भविष्य उज्जवल हो, युवाओं के हाथों में काम हो. इन सबके लिए भूपेश सरकार बेरोजगारी भत्ता चालू की है, ताकि पढ़ाई कर रहे और नौकरी की तैयारी में लगे युवाओं को आर्थिक मदद मिल सके. प्रदेश के ऐसे युवा जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से उन्हें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी सहित अन्य खर्चे उठाने में काफी परेशानी उठानी पड़ती है. इस योजना के तहत मिली राशि से वे अपनी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं. यह योजना अनेक युवाओं के भविष्य को एक नया आयाम देने में सहायक बन गया है.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब तक 1 लाख 16 हजार से ज्यादा युवाओं के खाते में लगभग राशि 80.64 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर युवाओं के चहेरे पर मुस्कान बिखेरी है. इस योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग देने की भी सुविधा है, जिससे उनको रोजगार मुहैया कराया जा सके. 2500 रुपए मिलने से बेरोजगार युवाओं की अपने माता-पिता व अन्य पर निर्भरता कम हो रही है. इस योजना को लेकर युवाओं का कहना है कि उनके संघर्ष के दिनों का दर्द कुछ कम हो रहा है. जेब खर्च के कारण परिवार पर निर्भरता से कुछ राहत मिल रही है.

बेरोजगारी भत्ते की कहानी बेरोजगारों की जुबानी

बेरोजगारी भत्ते को लेकर धमतरी जिले के रूद्री के पास का गांव बरारी के गजानंद ध्रुव ने कहा कि मेरे माता पिता पत्थर की खदान में रोजी मजदूरी करते हैं. मजदूरी कर मेरी शादी किए हैं. मै खुद किराया भंडार में काम करता हूं. आगे की पढ़ाई में पैसा नहीं होने के कारण से बाधा हो रही थी. बेरोजगारी भत्ता मिलने से अब मैं खुश हूं. पैसे से मैं पढ़ाई के लिए कापी-पुस्तक खरीद लेता हूं, जो पैसा बच जा रहा उससे समान भी खरीद लेता हूं. आगे की पढ़ाई अब बांधा नहीं होगी.

80 करोड़ से ज्यादा रुपए की आर्थिक सहायता

भूपेश सरकार राज्य में अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता दे रही है. तीन महीनों में राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के खातों में 80 करोड़ 64 लाख 25 हजार रुपए राशि सीधे भेजी है. बता दें कि पहली किस्त के रूप में राज्य सरकार ने 66265 बेरोजगार युवाओं को 17.50 करोड़ रुपए दिए थे. दूसरे किस्त के रूप में 1 लाख 5 हजार से अधिक बेरोजगार युवाओं को 32.35 करोड़ रुपए और तीसरे किस्त के रूप में 116737 युवाओं को 31.69 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं.

कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से 3 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण

राज्य सरकार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के साथ ही कौशल प्रशिक्षण भी दे रही है. इसके तहत मशीन ऑपरेटर, टैक्सी ड्राईवर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जा रहा है. राज्य के विभिन्न संस्थानों में 3318 से ज्यादा युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं.

भत्ते की पात्रता

आयु सीमा 18 से 35 वर्ष
2.5 लाख रुपए तक परिवार की वार्षिक आय
1 अप्रैल 2023 को 2 वर्ष पुराना रोजगार पंजीयन
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
मूल निवासी प्रमाण पत्र
जन्मतिथि के लिए 10वीं की मार्कशीट/प्रमाणपत्र
12 वीं की मार्कशीट, प्रमाणपत्र
आधार कार्ड और रोजगार पंजीयन कार्ड
पासपोर्ट साइज फोटो
गत 1 वर्ष की परिवार की आय का प्रमाण पत्र
आवेदन की प्रक्रिया
केवल ऑनलाईन आवेदन
रोजगार कार्यालय के पंजीयन क्रमांक
मोबाइल नंबर अनिवार्य
आधार अगर राशन कार्ड में ना हो तो आधार कार्ड अनिवार्य
बैंक खाता जानकारी डी.बी.टी. के लिये
कौशल प्रशिक्षण हेतु चॉयस

मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत छत्तीसगढ़ को कुपोषण एवं एनीमिया मुक्त बनाने के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं. इसके तहत आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों और महिलाओं को पौष्टिक गरम भोजन दिया जा रहा है. इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. कई बच्चों के चेहरों पर मुस्कान फिर लौट आई है.

विशेष - नन्हे भियान की लौटी मुस्कान: पौष्टिक खान पान और देखभाल से हुआ कुपोषण मुक्त, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से मिला नया जीवनदान

विगत साढ़े चार साल में लगभग 2 लाख 65 हजार बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं और डेढ़ लाख महिलाएं एनीमिया से बाहर आ गई हैं. इनमें महासमुंद जिले के सेक्टर पटपरपाली के साल्टेभाठा पंचायत के बैगा खम्हरिया गांव की टोमेश्वरी पटेल एवं नारद पटेल का पुत्र भियान पटेल भी शामिल है. एक समय था जब नन्हे भियान का वजन निरंतर कम होता जा रहा था जिससे वह गंभीर कुपोषण का शिकार हो गया. उसका वजन घटकर 7.200 किलोग्राम हो गया था. भियान की खाने के प्रति उदासीनता बढ़ती जा रही थी और वह गुमसुम सा होने लगा था, जबकि उसकी उम्र के अन्य बच्चे स्वस्थ और चंचल थे. गृहभेंट और वृद्धि निगरानी के के लिए गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा उसके परिवार से इस संबंध में चर्चा की और पोषण संबंधी जानकारी दी गई.

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी बैगा खम्हरिया में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत रोज गर्म पोष्टिक भोजन देने की वजह से पांचवें माह में ही उसके वजन में दो किलो की बढ़ौतरी हो गई. इससे वह कुपोषण के मध्यम श्रेणी में आ गया. पौष्टिक आहार और नियमित देखभाल से एक साल के भीतर उसका वजन बढ़कर 5 किलो हो गया है. गंभीर कुपोषण से मुक्त होकर अब सामान्य श्रेणी में आ गया है. इससे नन्हे भियान के चेहरे पर मुस्कान फिर लौट आई है. अधिकारियों ने बताया कि मई 2022 को भियान का वजन लेने पर पता चला कि उसका वजन 7.200 किलोग्राम है.

उम्र के अनुसार उसका वजन निर्धारित सीमा से बहुत कम था, इसलिए उसे गंभीर कुपोषण श्रेणी में रखा गया. आंगनबाड़ी केन्द्र में उसे धीरे-धीरे रेडी टू ईट खिलाने और खिचड़ी खिलाने का प्रयास शुरू किया गया. माता-पिता को भी समझाइश दी गई. बच्चों के साथ खेल खेल में खिलाने का प्रयास किया गया. इससे उसकी खाने के प्रति उसकी रूचि बढ़ने लगी. भियान को लगातार निगरानी में रखकर परिवारजनों का निरंतर फॉलोअप किया गया. इससे गंभीर कुपोषण के स्तर से ऊपर उठता हुआ भियान 10 अक्टूबर 2022 को मध्यम की श्रेणी में आ गया. इससे उसके परिवार वाले बहुत खुश हुए और उनका विश्वास भी बढ़ा. अब भियान 7.2 कि. ग्रा. से 11.9 किग्रा तक सफर कर सामान्य स्तर पर आ गया.

छोटी बचत पर सरकार ने बढ़ाई ब्याज दर

छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों पर फैसला आ गया है. सरकार ने ब्याज दर बढ़ाने का फैसला किया है. सरकार ने जुलाई-सितंबर 2023 तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 10 से 30 आधार अंक की बढ़ोतरी की है.

वित्त मंत्रालय ने 30 जून 2023 को जारी एक सर्कुलर के जरिए यह घोषणा की. यह नई दर 01 जुलाई से 30 सितंबर 2023 तक की तिमाही के लिए लागू होगी.

इन योजनाओं पर बढ़ी ब्याज दर

1 और 2 साल की पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, 5 साल की आवर्ती जमा जैसी योजनाओं की ब्याज दरें बढ़ा दी गई हैं.

वित्त मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि एक साल की सावधि जमा योजना पर ब्याज दर 6.8 फीसदी से बढ़ाकर 6.9 फीसदी, दो साल की योजना पर 6.9 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी और पांच साल की सावधि जमा योजना पर ब्याज दर 6.9 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी कर दी गई है. आवर्ती जमा पर देय ब्याज दर 6.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दी गई है.

इन योजनाओं पर ब्याज दर नहीं बढ़ी

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) पर ब्याज दर 8.2 प्रतिशत, सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) पर ब्याज दर 7.1 प्रतिशत, किसान विकास पत्र (केवीपी) पर ब्याज दर 7.5 प्रतिशत रखी गई है. केवल प्रतिशत.

इसके अलावा राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र पर ब्याज दर 7.7 फीसदी, सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर ब्याज दर 8 फीसदी और मासिक आय खाता योजना पर ब्याज दर 7.4 फीसदी रखी गई है. आपको बता दें कि सरकार द्वारा हर तिमाही में छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों की समीक्षा की जाती है.

पिछली घोषणा में कितनी बढ़ी थी दरें?

आपको बता दें कि पिछली घोषणा में सरकार ने अप्रैल-जून 2023 तिमाही के लिए अधिकांश लघु बचत ब्याज दरों में 70 आधार अंक (बीपीएस) तक की बढ़ोतरी की घोषणा की थी.

निजी बैंकों को महिला सम्मान बचत फॉर्म देने की मिली इजाजत

वित्त मंत्रालय ने आज निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले सभी सरकारी और निजी बैंकों को महिला सम्मान बचत फॉर्म 2023 जारी करने की अनुमति दे दी है. मंत्रालय ने इसके लिए जरूरी अधिसूचना 27 जून 2023 को जारी कर दी है.

इस कदम का उद्देश्य इस योजना को अधिकतम विस्तार देकर महिलाओं को बेहतर वित्तीय स्वतंत्रता देना है. इसकी घोषणा आम बजट 2023-24 में की गई थी.

इसके तहत 7.5 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर का भुगतान किया जाता है और तिमाही आधार पर ब्याज की गणना करने की व्यवस्था है. इस तरह सालाना देय ब्याज दर करीब 7.7 फीसदी हो जाती है. इसमें न्यूनतम एक हजार रुपये और अधिकतम दो लाख रुपये जमा करने की सुविधा है.

सीएम भूपेश के नए पुलिस रेंज के गठन से छत्तीसगढ़ की पोलिसिंग में आएगा बड़ा बदलाव, अपराधों पर लगेगा अंकुश

> रायपुर. प्रदेश में आम जनता की सुविधा, बेहतर पुलिसिंग और आपराधिक प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए नए पुलिस रेंजों का गठन किया गया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रदेश में बेहतर कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि पुराने पुलिस रेंजों का पुनर्गठन करते हुए नए पुलिस रेंज गठित किए गए है.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर कळच अशोक जुनेजा ने राज्य में छत्तीसगढ़ पुलिस में पुलिस रेंज का पुनर्गठन किया है. पुलिस रेंज के पुनर्गठन से जहां आम जनता को सुविधा होगी वहीं बेहतर पुलिसिंग, अपराधों की रोकथाम, आपराधिक प्रकरणों के त्वरित निराकरण और बेहतर कानून एवं व्यवस्था में काफी मदद मिलेगी. रेंजों के पुनर्गठन में रायपुर रेंज को दो भागों में विभक्त किया गया है. रायपुर रेंज में जिला रायपुर रहेगा. इसी तरह रायपुर ग्रामीण रेंज में धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद तथा बलौदा बाजार-भाटापारा जिला को शामिल किया गया है. दुर्ग रेंज में जिला दुर्ग, बेमेतरा तथा बालोद रहेंगे. राजनांदगांव रेंज में जिला

राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़-छुई खदान-गंडई तथा मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी को शामिल किया गया है. बिलासपुर रेंज में जिला बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, जांजगीर-चांपा, सक्ति, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही तथा जशपुर रहेंगे. बिलासपुर रेंज आईजी के अधीन डीआईजी रायगढ़ रहेंगे. डीआईजी रायगढ़ के अंतर्गत जिला रायगढ़, सक्ति तथा जशपुर रहेंगे. सरगुजा रेंज में जिला सरगुजा,कोरिया,सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज तथा एमसीबी रहेंगे. बस्तर रेंज में जिला बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर तथा सुकमा रहेंगे. आई जी बस्तर के अधीन 2 डीआईजी रहेंगे. डीआईजी दंतेवाडा के अंतर्गत जिला दंतेवाड़ा, सुकमा तथा बीजापुर जिले रहेंगे. डीआईजी कांकेर के अंतर्गत जिला कांकेर, नारायणपुर तथा कोंडागांव रहेंगे.

वहीँ, DGP अशोक जुनेजा ने बीते शुक्रवार को प्रदेश के सभी पुलिस महानिरीक्षकों एवं पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली. बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव-2023 की सुरक्षा व्यवस्था, नशीले पदार्थों, अवैध शराब, जुआं-सट्टा, ऑनलाईन गेम्बलिंग एवं गुण्डा बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही की रेंजवार समीक्षा की गयी एवं इसके विरूद्ध सख्त व प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये . पुलिस महानिदेशक द्वारा अभ्यस्त अपराधियों को सूचीबद्ध करने, उनके विरूद्ध रासुका तथा जिला बदर के तहत कार्यवाही करने, वारंटियों के विरूद्ध अभियान चला कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये.

DGP द्वारा चिटफण्ड कंपनियों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही की समीक्षा की गयी एवं पुलिस महानिरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि अभियोजन शाखाओं एवं जिला कलेक्टरों से समन्वय स्थापित कर निवेशकों की धन वापसी के लिये लगातार प्रभावी कार्यवाही करें. आगामी चुनाव को देखते हुए प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा व संचार व्यवस्था की समीक्षा की गयी एवं सीमावर्ती जिलों के समकक्ष अधिकारियों से बैठक हेतु निर्देशित किया गया. बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वय हिमांशु गुप्ता एवं प्रदीप गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षकगण अजय यादव, आनंद छाबड़ा, पी. सुंदरराज, सुशील द्विवेदी, बीएन मीणा, अंकित गर्ग, संजीव शुक्ला, राहुल भगत, आरिफ शेख, रामगोपाल गर्ग भी उपस्थित रहे.

सीएम भूपेश की उपस्थिति में टाटा टेक्नोलॉजीस के साथ एमओयू, 10 हजार युवा होंगे लाभान्वित

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में आज विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 36 शासकीय आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 1188.36 करोड़ की परियोजना पर तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग और टाटा टेक्नोलॉजीस के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए.

एमओयू के तहत टाटा टेक्नोलॉजीस द्वारा राज्य के 36 आईटीआई में युवाओं को 6 नए ट्रेडों में तथा 23 शॉर्ट टर्म कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा. टाटा टेक्नोलॉजीस द्वारा राज्य के चयनित आईटीआई में अत्याधुनिक तकनीकी वर्कशॉप की स्थापना तथा प्रशिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा राज्य के युवाओं को बड़ी कम्पनियों में प्लेसमेंट दिलाने में टाटा और उनकी सहयोगी कंपनी सहयोग करेंगी.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के संचालक अवनीश शरण तथा टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के प्रेसिडेंट पवन भगेरिया ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए. इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री उमेश पटेल, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला, सचिव टोपेश्वर वर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आईटीआई के उन्नयन और आधुनिकीकरण से राज्य के युवाओं को अपने कौशल को विकसित करने का अच्छा अवसर मिलेगा. उन्होंने कहा कि रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक नवाचार किए गए हैं, जिससे किसानों, मजदूरों, वनांचलों में रहने वाले आदिवासियों की आय में वृद्धि हुई है. पिछले साढ़े चार वर्षों में लोगों की जेब में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग एक लाख 60 हजार करोड़ रूपए की राशि डाली गई है, इससे व्यापार और उद्योगों को गति मिली है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश है कि गांव उत्पादन का केंद्र और शहर व्यापार के केंद्र के रूप में स्थापित हों. छत्तीसगढ़ में खेती-किसानी लाभप्रद बनने से शहरों से लोग गांव की ओर आ रहे हैं.

रीपा को आधुनिक बनाने टाटा टेक्नोलॉजीस से सहयोग का आग्रह

मुख्यमंत्री बघेल ने टाटा टेक्नोलॉजीस के अधिकारियों से कहा कि गांव में छोटे-मोटे उद्योग स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए गए हैं, जहां व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए जमीन, बिजली, पानी, शेड, प्रशिक्षण, वाई-फाई की सुविधा एवं बैंकिंग लिंकेज उपलब्ध कराया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने टाटा टेक्नोलॉजीस के अधिकारियों से रीपा तथा शहरी औद्योगिक केंद्रों को आधुनिक उद्योगों और नई तकनीक से लैस कर और अधिक विकसित करने में सहयोग का आग्रह किया. टाटा टेक्नोलॉजीस के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और यहां रोजगार के अवसर विकसित करने के राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की.

इन आईटीआई का होगा उन्नयन

टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटड के सहयोग से जिन आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा उनमें शासकीय आई.टी.आई. - बैकुण्ठपुर, ओड़गी वाड्रफनगर, मैनपाट, बगीचा, लोरमी, कोनी- बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, अकलतरा, हसौद, रायगढ़, खरसिया, राजनांदगांव, डोंगरगांव, मानपुर, छुईखदान, पण्डरिया, गुण्डरदेही, दल्लीराजहरा, गुरूर, दुर्ग, पाटन, धरसींवा, हीरापुर, आरंग, अभनपुर, भाटापारा, सिमगा, बागबाहरा, पिथौरा, कांकेर, अंतागढ़, चारामा, नगरनार एवं दंतेवाड़ा शामिल हैं.

6 नवीन तकनीकी ट्रेडों में मिलेगा प्रशिक्षण

आईटीआई उन्नयन परियोजना के अंतर्गत राज्य के युवाओं को विश्व स्तर के अत्याधुनिक निम्नलिखित 6 नवीन तकनीकी ट्रेडों में प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त होगी. इसमें एक वर्षीय ट्रेड में आर्टीजन यूजिंग एडवांस टूल, इंडस्ट्रीयल रोबोटिक्स एण्ड डिजिटल मैन्यूफैचरिंग टेक्निशियन, मैन्यूफैचरिंग प्रोसेस कण्ट्रोल एण्ड ऑटोमेशन शामिल हैं. इसी प्रकार दो वर्षीय ट्रेड में एडवांस सी.एन.सी. मशीनिंग, बेसिक डिजायनर एण्ड वर्चुअल वेरिफायर (मैकेनिकल), मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल के ट्रेड शामिल हैं.

अत्याधुनिक तकनीकी वर्कशॉप की होगी स्थापना: 10 हजार युवा होंगे लाभान्वित

टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड द्वारा चयनित प्रत्येक आईटीआई में अत्याधुनिक तकनीकी वर्कशॉप की स्थापना की जाएगी तथा प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रत्येक आईटीआई में प्रारंभ में दो प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. प्रशिक्षित युवाओं के प्लेसमेंट में टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड एवं उसके सहयोगी उद्योग सहयोग प्रदान करेंगे. योजना से प्रतिवर्ष लगभग 10 हजार युवा लाभान्वित होंगे.

गौरतलब है कि टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के सहयोग से राज्य के तकनीकी संस्थानों को टेक्नोलॉजिक हब के रूप में विकसित करने तथा कृषि अनुसंधान व नवाचार केंन्द्रों के रूप में उन्नयन हेतु राज्य योजना आयोग एवं टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के मध्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में 01 अक्टूबर 2022 को एमओयू किया गया था. इसकी अगली कड़ी के रूप में आज टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के सहयोग से राज्य की निम्नलिखित 36 शासकीय आई.टी.आई. के उन्नयन हेतु एमओयू किया गया.

शिक्षाकर्मी की नौकरी छोड़ कर मोहन मरकाम पहुंचे राजनीति में, पीसीसी चीफ के बाद अब बने मंत्री

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री बनाए गए मोहन मरकाम शिक्षा कर्मी रहे हैं. वे बस्तर संभाग के कोंडगांव से दूसरी बार के विधायक हैं. मरकाम का जन्म 15 सितंबर, 1967 को ग्राम-टेड़मुड़ा, जिला-कोण्डागांव में हुआ था. उनके पिता का नाम स्व. श्री भीखराय मरकाम है. मरकाम ने दो विवाह किया है. उनकी पहली शादी 24 अप्रैल, 1998 को ललिता मरकाम से और दूसरी 31 जुलाई, 2010 मैना मरकाम से हुई. मरकाम के तीन पुत्र और एक पुत्री है.

मरकाम भूगोल विषय में एमए हैं और कृषि के साथ व्यवसाय उनकी जीविका का साधन है. समाजसेवा, खेलकूद, धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना उनकी रुचि में शामिल हैं. राज्य विधानसभा से 2017-18 में उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित मरकाम नई दिल्ली में राजपथ पर गणतंत्र दिवस अवसर पर होने वाले परेड बतौर एनसीसी कैडेट शामिल हो चुके हैं. उन्होंने मलेशिया की यात्रा की है.

मरकाम 2010 में जिला प्रतिनिधि बने. पहले वे शिक्षा कर्मी वर्ग - 2 और फिर शिक्षा कर्मी वर्ग - 1 के पद पर काम कर चुके हैं. एलआईसी में मरकाम विकास अधिकारी और सीनियर एजेन्सी मैनेजर के पद पर काम कर चुके हैं.

मरकाम 2013 में प्रथम बार और 2018 में दूसरी बार विधायक चुने गए.

इन शेयर्स ने निवेशकों को बना दिया अमीर, जानिए किसने दिया 2500% से ज्यादा रिटर्न ?

कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली छमाही में घरेलू शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला. इस बीच, दलाल स्ट्रीट पर 33 स्टॉक निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न देने में कामयाब रहे. इसका मतलब है कि इस साल जनवरी से अब तक 33 शेयरों ने निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है.

इसी अवधि में बीएसई सेंसेक्स में 3.5 फीसदी का उछाल देखने को मिला. पिछले सप्ताह बीएसई सेंसेक्स अपने जीवनकाल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. इसी अवधि में निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले 33 शेयरों में से अधिकांश मिडकैप और स्मॉलकैप श्रेणियों से आते हैं. मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले शेयरों की इस सूची में केवल 500 करोड़ रुपये से अधिक वैल्यूएशन वाले शेयरों को शामिल किया गया है.

2023 में इन शेयरों ने मचाई धूम

इस लिस्ट में रेमेडियम लाइफकेयर का शेयर सबसे पहले आता है. इस साल अब तक इस शेयर में 2573 फीसदी का उछाल देखने को मिला है. आंध्रा सीमेंट्स का स्टॉक सूची में दूसरे स्थान पर है. इस शेयर ने 1,392 फीसदी का रिटर्न दिया. इसी तरह K-R रेल इंजीनियरिंग के शेयर में 689 फीसदी की तेजी देखी गई.

सूर्यलता स्पिनिंग मिल्स के शेयर में 310 फीसदी का उछाल देखने को मिला है.

जेआईटीएफ इंफ्रा लॉजिस्टिक्स में 271 फीसदी की बढ़त देखने को मिली है. इसी तरह जेआईटीएफ इन्फ्रालॉजिस्टिक्स में 271 फीसदी की तेजी देखने को मिली है.

इस दौरान ऑरियनप्रो सॉल्यूशंस के शेयर में 200 फीसदी की तेजी आई. ईएफसी में इस साल अब तक 175 फीसदी का उछाल देखने को मिला है. न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में अब तक 172 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है. मास्टर ट्रस्ट के शेयरों में 160 फीसदी और सैकसॉफ्ट के शेयरों में 160 फीसदी का उछाल आया.

इन 33 शेयरों में से छह शेयर पूंजीगत सामान क्षेत्र के हैं. इसी तरह, छह स्टॉक सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित हैं. इस अवधि के दौरान लार्ज कैप आईटी शेयरों का प्रदर्शन कमजोर रहा. वहीं, बड़ी संख्या में निवेशकों ने मिडकैप और स्मॉलकैप टेक्नोलॉजी शेयरों में दिलचस्पी दिखाई.

कैबिनेट का फैसला: सरकारी भर्ती में छूट, मिलेगा पट्टा, उद्योगों को छूट, बीमार और बंद कारखानों के लिए पैकेज, अनुपूरक मंजूर

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने नवा रायपुर में प्रभावितों को पट्टा देने का फैसला किया है. बीमार और बंद उद्योगों को भी पैकेज देने का निर्णय किया गया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. इसमें सरकारी भर्ती में छूट देने के साथ ही उद्योगों की स्थापना में रियायत देने का फैसला किया गया है.

कैबिनेट ने राज्य के प्रथम अनूपूरक अनुमान वर्ष 2023-24 को मंजूर दी. इसके करीब तीन हजार करोड़ रुपये के होने का अनुमान है. बैठक के बाद वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद अकबर ने कैबिनेट लिए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी.

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के पुनर्वास योजना के अंतर्गत यथा संशोधित कण्डिका 5.5 के अनुसार ग्राम राखी के परियोजना प्रभावितों को पात्रता अनुसार बाड़ी हेतु खुली भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया.

छत्तीसगढ़ राजस्व (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 1985 की अनुसूची- चार को शिथिल करते हुए ऑडिटर / सहायक अधीक्षक से अधीक्षक (रा.) के 38 रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु केवल एक ब.ार तीन वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया

छत्तीसगढ़ ब्राम्हण समुदाय जिला बिलासपुर को आबंटित भूमि में छूट प्रदाय करने का निर्णय लिया गया.

खरीफ सीजन को लेकर भी चर्चा

बैठक में कैबिनेट ने खरीफ सीजन की खेती को लेकर अनौपचारिक चर्चा हुई. सूत्रों के अनुसार अभी तक हुई बारिश और रोपाई सहित खेती की अन्य गतिविधियों पर कृषि विभाग की तरफ से विस्तार से जानकारी दी गई. बताया जा रहा है कि अफसरों ने इस वर्ष भी धान की खेती का रकबा बढ़ने का अनुमान जताया है. अफसरों ने बताया कि इस मामले में मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक के बाद कैबिनेट की अगली बैठक में इस विषय पर विस्तार से चर्चा होगी.

लेयर -1 के 12 ग्रामों में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के भूमि स्वामित्व की भूमि पर काबिज पात्र परिवारों को निर्धारित सीमा अनुसार बसाहट पट्टा प्रदान करने का निर्णय लिया गया.

छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न वर्गों के लिए उद्योग स्थापना के लिए विभिन्न प्रकार की छूट, अनुदान और रियायतें घोषित की गई है. राज्य में वृहद, मेगा, अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत षविशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज क्रियान्वयन नियम-2019 को समावेशित करने का निर्णय लिया गया.

छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 में व्हीकल स्क्रेपिंग पॉलिसी को शामिल करने के साथ ही स्टॉम्प शुल्क से छूट, मण्डी शुल्क से छूट, राज्य में बंद और बीमार उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज परिवहन अनुदान, विद्युत शुल्क छूट संबंधित संशोधनों के प्रास्ताव का अनुमोदन किया गया.

गूगल टीवी सपोर्ट के साथ Sony Bravia XR X90L भारत में लॉन्च

सोनी ने इंडियन मार्केट में Sony Bravia XR X90L टेलीविजन सीरीज लॉन्च की है. सीरीज X90K रेंज की अपग्रेडेड वर्जन है, जिसे जून 2022 में लॉन्च किया गया था, और इसमें फुल- ट्रिलुमिनोस क्वांटम डॉट एलईडी डिस्प्ले पैनल है. हाई-एंड टीवी रेंज के लिए इसकी कीमतें 1,39,990 रुपये से शुरू होती हैं. 55 इंच से 75 इंच तक के साइज में उपलब्ध, सोनी ब्राविया एक्सआर एक्स90एल टीवी सोनी की अधिक लोकप्रिय प्रीमियम टेलीविजन सीरीज में से एक है. सारे वेरिएंट डॉल्बी विजन को सपोर्ट करते हैं और अल्ट्रा-एचडी स्क्रीन के साथ आते हैं.

Sony Bravia XR X90L की कीमत और उपलब्धता

Sony Bravia XR X90L सीरीज अलग-अलग साइज के तीन वेरिएंट में उपलब्ध है. 55-इंच XR-55X90L वेरिएंट की कीमत 1,39,990 रुपये, जबकि 65-इंच XR-65X90L वेरिएंट की कीमत 1,79,990 है. ये दोनों अब भारत में सोनी के सेल्स नेटवर्क के जरिए खरीदने के लिए उपलब्ध हैं, जिसमें सोनी सेंटर स्टोर, प्रमुख इलेक्ट्रानिक्स स्टोर और मुख्य ऑनलाइन रिटेलर्स शामिल हैं. इसका तीसरा 75-इंच XR-75X90L अभी लॉन्च नहीं किया गया है. इसे बाद की तारीख में खरीदने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.

Sony Bravia XR X90L की फीचर्स

फीचर्स की बात करें, तो सोनी के तीनों टीवी Ultra-HD full-array LED डिस्प्ले के साथ आते हैं. इनका रेजलूशन 3840x2160 पिक्सल है. डिस्प्ले में सोनी की Triluminos quantum-कवज टेक्नोलॉजी दी गई है. टीवी में Dolby Atmos और Dolby Vision का सपोर्ट मिलता है. यह टीवी IMAX Enhanced सर्टिफाइड हैं, जो कि आपको शानदार विजुअल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे.

ऑडियो की बात करें, तो टीवी में X-balanced स्पीकर दिया गया है, जो कि Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आता है. Sony Bravia XR-X90L सीरीज Android TV पर काम करते हैं. इसके साथ इसमें Google TV यूजर इंटरफेस मिलता है. इसका मतलब यह है कि इन टीवी में गूगल असिस्टेंट के साथ-साथ 10,000 से ज्यादा ऐप्स का सपोर्ट गूगल प्ले स्टोर से प्राप्त होगा.

इनमें Bravia Core स्ट्रीमिंग सर्विस भी मिलती है. अन्य फीचर्स में Sony Cognitive Processor XR शामिल है. जैसे कि हमने बताया इन टीवी में X-Protection PRO टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कि टीवी को डस्ट और ह्यूमिडिटी रसिस्टेंट बनाती है.

आ रहा OnePlus का सबसे शक्तिशाली फोन, दुनिया का पहला जिसमें 24GB रैम और 1TB स्टोरेज

OnePlus दो फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर काम कर रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इनके नाम OnePlus 12 और OnePlus Ace 2 Pro होंगे. इन स्मार्टफोन को लेकर लीक्स सामने आने लगे हैं और कंपनी भी बड़ी तैयारी कर रही है. लेटेस्ट लीक्स में दावा किया है कि वनप्लस 24GB Ram वाला फोन ला रहा है. वनप्लस अब Red Magic 8S Pro और iQOO 11S को टक्कर देने के लिए अपना नया हैंडसेट लॉन्च कर सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका नाम OnePlus Ace 2 Pro हो सकता है. अभी कंपनी की तरफ से इसके फीचर्स कंफर्म नहीं किए हैं. अभी तक ये क्लियर नहीं है कि 24GB RAM में कितनी वर्चुअल रैम होगी.

इससे पहले डिजिटल चैट स्टेशन ने बताया था कि फोन में Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है.

यह स्मार्टफोन 150W फास्ट चार्जिंग के साथ आ सकता है. कंपनी इसका 100W चार्जिंग वाला वेरिएंट भी लॉन्च कर सकती है, जो 5 हजार एमएएच बैटरी को पावर देगा. रिपोर्ट्स पर भरोसा किया जाए तो OnePlus Ace 2 Pro में 1.5K रेजॉलूशन वाला डिस्प्ले दिया जाएगा, यह वही डिस्प्ले होगा जो ओपो रेनो 10 प्रो फोन में था. डिस्प्ले में कर्व्ड ऐजेस और स्लिम बेजेल्स होंगे. इस स्क्रीन की सप्लाई BOE द्वारा की जाएगी.

कैमरा और बैटरी भी जबर्दस्त

फोटोग्राफी के लिए, फोन में एफ/1.79 अपर्चर के साथ 64-मेगापिक्सेल ओमनीविजन OV64M प्राइमरी सेंसर, अल्ट्रा-वाइड कैमरा लेंस के साथ 8-मेगापिक्सेल सोनी IMX355 सेंसर और 2-मेगापिक्सेल गैलेक्सीकोर GC02M सेंसर शामिल होने की संभावना है. कहा जा रहा है कि अपकमिंग वनप्लस ऐस 2 प्रो फोन में 150W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5000mAh की बैटरी होगी.

बता दें कि, OnePlus Ace Pro को भारत में OnePlus 10T मॉनीकर के साथ लॉन्च किया गया था. ऐसे में, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि OnePlus Ace 2 Pro को भारत में OnePlus 11T मॉनीकर के साथ लॉन्च किए जाने की संभावना है.

क्या आप भी लोन के बोझ तले दबे हैं, जानिए पाएं जल्द छुटकारा ?

होम लोन एक बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी है, जिसे समय पर चुकाना जरूरी है. पिछले कुछ महीनों से आरबीआई ने लोन की ब्याज दरों में कई बार बढ़ोतरी की है.

मौजूदा समय में लोन पर ब्याज 6.5 फीसदी से बढ़कर 9 फीसदी हो गया है. वहीं, अप्रैल में 20 साल की अवधि पर लिए गए होम लोन की अवधि 30 से बढ़कर 32 साल हो गई है. ऐसे में इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए.

होम लोन को कम करने के लिए लंबी अवधि की बजाय 10 से 15 साल की ही अवधि चुनें, ताकि आपको ज्यादा ब्याज न देना पड़े और लोन भी चुका दिया जाए.

जब भी आपके पास रकम हो तो प्रीपेमेंट कर लें. इसके जरिए आप लोन का 60 से 70 फीसदी भुगतान करते हैं, जिससे लोन की रकम कम करके अपनी ईएमआई बढ़ाने पर ध्यान दें, ताकि आपका लोन जल्द से जल्द चुकाया जा सके.

आमदनी के साथ आप ईएमआई भी बढ़ा सकते हैं. 20 साल के लिए 7.5 प्रतिशत पर 40 लाख रुपये के होम लोन पर ईएमआई 5,000 रुपये बढ़ाकर, कोई ब्याज खर्च में लगभग 8 लाख रुपये बचा सकता है और सात साल पहले कर्ज मुक्त हो सकता है.

विशेषज्ञों के मुताबिक, लोन प्रीपेमेंट तभी करना चाहिए जब आपके पास अतिरिक्त पैसा हो और आप जल्द से जल्द लोन चुकाना चाहते हों.

सभी प्रदेशवासियों को

स्वतंत्रता दिवस

के पावन पर हार्दिक शुभकामनाएं

श्री बृजमोहन अग्रवाल जी
पूर्व मंत्री
(विधायक, रायपुर दक्षिण)

मान. टी.एस. सिंहदेव
उपमुख्यमंत्री
मान. चरणदास महंत
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा
मान. दीपक बैज
सांसद
मान. रविन्द्र चौबे
सहकारिता मंत्री, छ.ग. शासन
मान. मो. अकबर
वन मंत्री, छ.ग. शासन
मान. बैजनाथ चंद्राकर
प्राधिकृत अधिकारी
(केबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त)
छ.ग. राज्य सहकारी बैंक मर्या. रायपुर
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनायें
मान. भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
मान. सत्यनारायण शर्मा
वरिष्ठ विधायक एवं पूर्व मंत्री
110 वर्षों से किसानों की सेवा में समर्पित
छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे अग्रणी सहकारी बैंक
वर्ष 2022-23 में बैंक को राशि ₹14-23 करोड़ का शुद्ध लाभ
बैंक की मुख्य योजनाएं
• बैंक द्वारा कृषकों को कृषि ऋण दिनांक 01 अप्रैल 2014 से 0 (शून्य) बिना प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध।
• ग्रामीण कृषकों के लिये आवास निर्माण हेतु ₹ 1 लाख तक ऋण की सुविधा।
• बैंक द्वारा सहकारी समिति के माध्यम से कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड पर अधिकतम ₹5 लाख ऋण जिसमें 3 लाख नगद राशि एवं ₹2 लाख सामग्री ऋण की सुविधा।
• समर्थन मूल्य के अंतर्गत धान उपार्जन कार्य
• राजीव गांधी न्याय योजना।
• गोधन न्याय योजना।
बैंक की कार्यशील पूंजी 6560.61 करोड़
बैंक की अमानतें 4229.24 करोड़
बैंक द्वारा रायपुर, महासमुन्द, धमतरी, बलौदाबाजार-भाटापारा, सारंगढ़-बिलाईगढ़, गरियाबंद जिलें में 64 कृषि एवं रायपुर राजधानी क्षेत्र में 6 अमानत शाखाओं का सफल संचालन
पंकज शर्मा
प्राधिकृत अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर (छत्तीसगढ़)
दूरभाष : 0771-4255400 | E-mail : jskbankraipur@gmail.com